

सिद्धार्थनगर। माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार दीवानी न्यायालय सिद्धार्थनगर के मुख्यालय परिसर में स्थित कैन्टीन फोटो कॉपी मय फोटोग्राफी की दुकान संख्या-01, जनरल स्टोर एवं बेकरी की दुकान, पान की दुकान तथा वाहन स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 29 मई 2026 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। जिस किसी इच्छुक व्यक्ति को उक्त नीलामी/ ठेका प्रक्रिया में भाग लेना हो, वह निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार नीलामी में प्रतिभाग कर सकता है। उक्त आशय की जानकारी नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं विशेष न्यायाधीश एस.सी. /एस.टी. एक्ट, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर, त्रिभुवन नाथ द्वारा दी गई।

सम्पादकीय

जिसका खमियाजा जरूरतमंद मरीजों को उठाना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में एक खराब सीटी स्कैनर की वजह से दुर्घटना पीड़ितों, कैंसर के मरीजों और हृदयाघात के रोगियों के उपचार में देरी होती है। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डब्ल्यूकेरों का हर एक खाली पद कमजोर वर्ग के लोगों को महंगे निजी अस्पतालों में उपचार के लिये धकेल देता है। यह विडंबना ही है कि ...

गुस्से की आवाज और जूते का लॉजिक

भारतीय संस्कृति में जूता सिर्फ पहना नहीं जाता, जरूरत पड़ने पर दिखाया भी जाता है। तभी तो हमारे गुस्से की आवाज पहले आती है हरियाणवी पूछता हैकूमनैं आंख दिखावै? हिंदी भाषी कहेंगे आप मुझे क्यों धूर रहे हो? इतनी लंबी लाइन बोलते—बोलते तो हमारा गुस्सा ही टंडा हो जाए! हरियाणवी का गुस्से में जवाब होगाकूमेरा जूता दिखै है ना। और सामने वाला समझ जाता है कि अब इतिहास लिखा जाएगा। हमारी बोली का गुस्सा क्यों खास है क्योंकि हमारे यहां गुस्सा भी देसी है। वो मिट्टी से जुड़ा है। वो जूते से शुरू होकर चप्पल तक जाता है और फिर मां के ‘एक झापड़ पड़ेगा’ पर आकर स्थिर हो जाता है। ब्रांडेड जूते इतने महंगे हो गये हैं कि दादाजी को पूछना पड़ता है— छोरे! प्लॉट ले रह्या है अक जूते? दार्शनिकों को तो यह भी कहना है कि चप्पल से बड़ा कोई कप्पल नहीं, एक खो जाये तो दूसरे का अस्तित्व ही खो जाता है। बड़े—बूढ़ों का कहना है कि जूता भी बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतना ही दिमाग तेज होगा। एक बात माननी पड़ेगी कि इंटरव्यू वाले दिन लड़के जूते ऐसे चमकाते हैं माने जूता ही इंटरव्यू देने जा रहा हो। ताऊ नया जूती पहन कर चौपाल में गया तो एक ने कह दिया— वाह ताऊ आज तो नयी जूती गाड़ कै आ रह्या है। ताऊ बोल्या— के होग्या फेर, पैर तो पुराने हैं। हमारे यहां जूता सिर्फ फुटवियर नहीं बल्कि एक विचारधारा है। भारतीय संस्कृति में जूता सिर्फ पहना नहीं जाता, जरूरत पड़ने पर दिखाया भी जाता है। तभी तो हमारे गुस्से की आवाज पहले आती है और लॉजिक बाद में। जूता छिपाई की रस्म शायियों में तो सालियां करती हैं पर मदिरें में जूता—चुराई की रस्म कौन साले करते हैं, आज तक नहीं पता चला। जूता चप्पल, झाड़ू, बेलन ये सब गुस्से के हथियार हैं। अपने यहां जब क्रोध सुलगने लग जाये तो गुस्से में कहा जाता है— जूता निकालूं क्या? मेरा मन सोचता है कि बेचारे अंग्रेज क्या निकालते होंगे? हमारे यहां तो बरसों पहले कहा गया कि लातों के भूत बातों से नहीं जूतों से मानते हैं। यह असल में एक सांस्कृतिक अलार्म है जो बताता है कि जहां कानून ना माना जाये वहां जूता लोकतंत्र संभाल लेता है। यह संवाद आखिरी सीटी है।

अफ्रीका में इबोला के मामले सामने आने से कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज पर कुछ यात्रियों के हंतावायरस के संक्रमित लोगों की खबर ने कोविड के दिनों की याद ताजा कर दी। छह साल पहले, मार्च 2020 में एक क्रूज जहाज रूबी प्रिसेस के सिडनी में डब्लूक होने के बाद कोविड फैल गया था। जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 575 लोग कोविड से संक्रमित थे। इसके बाद यह ...

कांगों में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि वहां युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है जिसे रोकने के लिए कम ही साधन हैं। वायरस संक्रमित लोगों में से एक—तिहाई लोगों की जान ले लेता है। वहीं हंतावायरस की नई चुनौती भी है। कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज, एमवी होडियस पर हंतावायरस के मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों में इबोला का प्रकोप स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। यह वायरस हफ्तों से दुनिया के एक ऐसे हिस्से में फैल रहा है, जहां गृह युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। साथ ही, इसमें शामिल इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है। इसलिए इस वायरस को रोकने के लिए अधिकारियों के पास कम ही साधन उपलब्ध हैं। यह वायरस संक्रमित लोगों में से लगभग एक—तिहाई लोगों की जान ले लेता है। यह इस महामारी के फैलने का एक बहुत ही नाजुक दौर है। विश्व स्वास्थ्य

महंगी मशीनें विलासिता नहीं बुनियादी जरूरत

गाल बजाते राजनेता और लोक कल्याणकारी होने का दावा करती सरकारों की नाक के नीचे सरकारी अस्पतालों की कैंसी बदहाली है, ये किसी से नहीं छिपा है। लोकलुभावन कार्यक्रमों पर पैसा पानी की तरह बहाने वाली सरकारों व मंत्रियों की प्राथमिकताओं में, वे सरकारी अस्पताल कभी नहीं रहे हैं, जो गरीबों व साध् नविहीन लोगों का अंतिम आश्रय होते हैं। कायदे से तो सरकारों को इस मुद्दे को प्राथमिकता मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्पतालों की दशा सुधारनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हर बार न्यायालय को ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सख्ती दिखाकर सरकारों को कार्रवाई करने को कहा जाता है। एक बार फिर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश से पंजाब तथा हरियाणा सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संचालकों को एक बेहद जरूरी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू सुविधाओं के साथ—साथ सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की उपलब्ध ता सुनिश्चित की जाए। निश्चित रूप से न्यायालय के इस तरह के सकारात्मक हस्तक्षेप से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सताधीशों के वायदों और उनके क्रियान्वयन के बीच बढ़घ्ती खाई ही उजागर होती है। वहीं अदालत की कार्यवाही के दौरान पंजाब सरकार की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य के 23 जिलों में से केवल छह जिला अस्पतालों में ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी ओर राज्य के अस्पतालों में दो हजार से अधिक जनरल मेडिकल ऑफिसरों के पद और अन्य सैकड़ों विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में कार्यशील आईसीयू की कमी है। अदालत ने हरियाणा सरकार से भी गहन देखभाल व निदान सुविधाओं की कमियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। निस्संदेह, इन खामियों से फिर उजागर हुआ है कि अनेक सरकारी अस्पतालों में महंगे विकित्सा उपकरण अक्सर बिना इस्तेमाल के या कम उपयोग में क्यों रहते हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भी गरीब व जरूरतमंद मरीजों की तात्कालिक जरूरतों को अनदेखा ही किया जाता है। न्यायालय की

इस बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि मौजूदा दौर में सीटी स्कैन,एमआरआई और आईसीयू तक मरीजों की पहुंच विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता बन गई है। जो इस बात पर भी बल देता है कि सरकारें जिला स्तरीय क्रियाशील बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय अनिश्चित काल तक आउटसोर्सिंग या रेफरल प्रणालियों पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली केवल खरीद की कमी से ही नहीं, बल्कि बिना योजना के भारी—भरकम खरीद की प्रवृत्ति से भी ग्रस्त है। वहीं दूसरी ओर अकसर तकनीशियनों की अनुपलब्धता से एमआरआई मशीनें स्थापित नहीं हो पाती हैं। वहीं अनुबंध समाप्त होने के कारण अक्सर वेंटिलेटर धूल खाते रहते हैं। दूसरी तरफ रेडियोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियरों की अनुपस्थिति के कारण निदान सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है। बार—बार की गई ऑडिट रिपोर्टें से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये के जीवन रक्षक उपकरण महीनों से लेकर वर्षों तक बेकार ही पड़े रहते हैं। जिसका खमियाजा जरूरतमंद मरीजों को उठाना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में एक खराब सीटी स्कैनर की वजह से दुर्घटना पीड़ितों, कैंसर के मरीजों और हृदयाघात के रोगियों के उपचार में देरी होती है। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का हर एक खाली पद कमजोर वर्ग के लोगों को महंगे निजी अस्पतालों में उपचार के लिये धकेल देता है। यह विडंबना ही है कि दूर—दराज के ग्रामीण इलाकों के मरीज अक्सर लंबी दूरी तय करके सरकारी अस्पतालों तक पहुंचते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उन्हे या तो मशीनें काम न करने वाली मिलती हैं या चलाने वाले कर्मचारी नहीं मिलते। निर्विवाद रूप से केवल मशीनें लगाने से ही मरीजों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सही मायनों में सरकारी अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही डॉक्टरों, तकनीशियनों आदि की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। वास्तव में किसी भी स्वास्थ्य सेवा का मूल्यांकन खरीदी गई महंगी मशीनों से नहीं, बल्कि सही समय पर उपचार का लाभ पाने वाले मरीजों की संख्या से होता है।

चुनावी तंत्र में भरोसा कायम रखने की चुनौती

देश में मतदाता सूची भी राजनीतिक यु) का मैदान बन चुकी है। बहस का मूल प्रश्न एसआईआर का होना या नहीं होना नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत की चुनावी प्रणाली आम नागरिक में भरोसा पैदा कर पा रही है? जब कोई मतदाता यह महसूस करने लगे कि उसका वोट सुरक्षित नहीं है या चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव है, तब लोकतंत्र केवल संवैधानिक ढांचा भर रह जाता है। चुनाव आयोग की भूमिका ...

एसआईआर का तीसरा चरण केवल वोटर लिस्ट सुधार कार्यक्रम नहीं। यह भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की परिपक्वता की एक साथ परीक्षा है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी, संतुलित और निष्पक्ष तरीके से पूरी होती है तो भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होकर उभरेगा। भारत में चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं होते, वे लोकतंत्र की सामूहिक वैधता का उत्सव भी होते हैं। लेकिन जब मतदाता सूची ही सवालों के घेरे में आ जाए, तब लोकतंत्र की पूरी संरचना बहस के केंद्र में आ खड़ी होती है। यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा चरण केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का संवेदनशील अध्याय बन गया है। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर लागू करने का कार्यक्रम घोषित किया है। इनमें ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, तथा चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। इनमें से कई राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को केवल ‘मतदाता

सूची सुधार अभियान’ मानकर नहीं देखा जाएगा। इसके राजनीतिक अर्थ, चुनावी प्रभाव व लोकतांत्रिक संकेत दूरगामी होंगे। चुनाव



आयोग का तर्क है कि इस मुहिम का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। मृत मतदाताओं के नाम हटाने हैं, डुप्लीकेट वोट समाप्त करने हैं, माइग्रेसन के कारण बदले पते अपडेट करने हैं और नए पात्र मतदाता जोड़ने हैं। सिद्धांततः इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति केवल सिद्धांतों से नहींया आशंकाओं व अनुभवों से भी संचालित होती है। ऐसे में एसआईआर तकनीकी प्रक्रिया कम और राजनीतिक बहस अधिक बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतदाता सूची को लेकर विवाद उठते रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगाते रहे कि बड़े पैमाने

पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं या फिर चुनावी लाभ के लिए वोटर लिस्ट में ‘मैनेजमेंट’ किया जा रहा है। हाल में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद यह बहस और तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है, चुनावी प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं। दूसरी ओर केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक हार की हताशा बताते हैं। यानी मतदाता सूची अब केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रहीय राजनीतिक विश्वास और अविश्वास की कसौटी बन चुकी है। यहीं बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने की निष्पक्ष प्रक्रिया है,या फिर राजनीति के ष्ठवीकरण में यह भी नया सियासी औजार बनता जा रहा है? सैद्धांतिक रूप से देखें तो एसआईआर की जरूरत है। इस विशाल देश में लगातार माइग्रेसन, शहरीकरण और जनसंख्या गतिशीलता के कारण मतदाता सूची को अद्यतन रखना बेहद कठिन कार्य है। करोड़ों लोग रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कारणों से लगातार स्थान बदलते हैं। लाखों लोग मृत्यु के बाद भी वर्षों तक वोटर लिस्ट में बने रहते हैं। डुप्लीकेट वोट भी हैं। यदि निर्वाचन आयोग समय—समय पर व्यापक

पुनरीक्षण न करे तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है, सत्यापन प्रक्रिया कई बार चयनात्मक दिखाई देती है। खासकर गरीब, प्रवासी, किरायेदार और हाशिये पर खड़े वर्गों के मतदाता सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन लोगों के पास स्थायी दस्तावेज नहीं, बार—बार पता बदलता है, या जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, वे सबसे पहले सूची से बाहर होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग दुनिया की सबसे विश्वसनीय चुनावी संस्थाओं में गिना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। ऐसे में एसआईआर उसके लिए भी बड़ी परीक्षा है। ऐसे में निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखना भी जरूरी होगा। यदि लाखों मतदाताओं के नाम कटते हैं तो आयोग को पारदर्शी तरीके से यह बताना होगा कि किन आधारों पर कार्रवाई हुई। लगभग सभी राजनीतिक दल सिद्धांततः ‘शुद्ध मतदाता सूची’ के पक्ष में हैं, लेकिन व्यवहार में हर दल की चिंता अपने वोट बैंक को लेकर है। यदि किसी राज्य में बड़ी संख्या में शहरी प्रवासी मतदाता सूची से बाहर होते हैं तो इसका प्रभाव अलग होगा। ग्रामीण इलाकों में नाम कटते हैं तो समीकरण अलग होंगे। यदि नए युवा मतदाता बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो चुनावी रुझान बदल सकते हैं। यानी एसआईआर चुनावी गणित का भी बड़ा कारक है।

हंतावायरस—इबोला से फिर स्वास्थ्य चुनौती

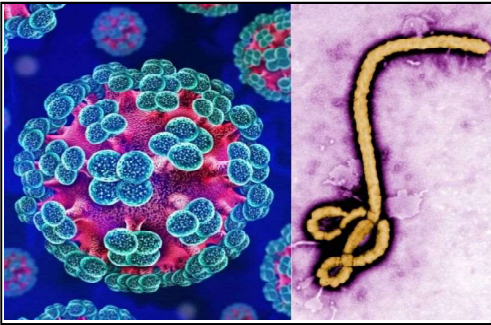
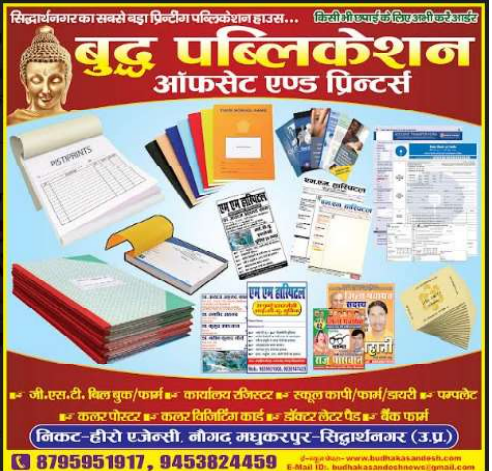
इसे ‘अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी’ घोषित किया है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कोविड जैसी किसी बड़ी महामारी के शुरुआती दौर में पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया के लिए इबोला से होने वाला खतरा अब भी कम है। वर्ष 2014—16 में इबोला महामारी के दौरान भी ब्रिटेन में इबोला के केवल तीन मामले सामने आए थे, और वे सभी स्वास्थ्यकर्मी थे जो स्पेक्छा से मदद के लिए आगे आए थे। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के पैडेमिक साइंसेज इंस्टिट्यूट की वैज्ञानिक डॉ. अमांडा रोजेक का कहना है कि नए प्रकोप पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी तालमेल की जरूरत है। युगांडा, दक्षिण सूडान और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह इबोला अब भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देशों को व्यापार और यात्रा के

घनिष्ठ संबंधों के कारण ‘उच्च जोखिम’ वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इबोला एक गंभीर और जानलेवा संक्रामक बीमारी है। दरअसल, इबोला वायरस स्वाभाविक रूप से जानवरों, मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन अगर लोग उनके सीधे संपर्क में आते हैं, तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। इस प्रकोप का कारण इबोला वायरस की बुंडिबुग्यो प्रजाति है। यह उन तीन प्रजातियों में से एक है, जिनके कारण

संक्रमण फैलता है। बुंडिबुग्यो ने पहले केवल दो बार प्रकोप फैलाया है। वर्ष 2007 और 2012 में इसने संक्रमित लोगों में से लगभग 30 प्रतिशत की जान ले ली थी। बुंडिबुग्यो वायरस स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां खड़ी करता है। इबोला वायरस की अन्य प्रजातियों के विपरीत बुंडिबुग्यो के लिए कोई भी स्वीकृत टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ प्रायोगिक दवाएं अवश्य मौजूद हैं। वायरस के संक्रमण की पुष्टि करने वाले टेस्ट बहुत कारगर नहीं हैं। इस प्रकोप के शुरुआती नतीजे इबोला वायरस के लिए नेगेटिव आए थे और वायरस की पुष्टि करने के लिए अधिक उन्नत प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। इसमें बुंडिबुग्यो भी शामिल है। ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ट्रूडी लैंग कहती हैं कि बुंडिबुग्यो से निपटना इस प्रकोप में एक बहुत बड़ी चिंता है।

समझा जाता है कि संक्रमण होने के दो से 21 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

शुरुआत में ये पलू के लक्षणों जैसे होते हैं जिनमें बुखार, सिरदर्द और थकान शामिल हैं। लेकिन जैसे—जैसे इबोला बढ़ता है, इससे उल्टी, दस्त और शरीर के अंगों का काम करना बंद हो जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कुछ मरीजों को शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव की समस्या भी हो जाती है। बुंडिबुग्यो वायरस को सीधे निशाना बनाने के लिए कोई भी स्वीकृत दवा उपलब्ध न होने के कारण इसका इलाज बेहतर सहायक देखभाल पर निर्भर करता है, जिसमें दर्द, अन्य संक्रमणों, शरीर में तरल पदार्थों और पोषण का प्रबंधन शामिल है।



प्रकोप जितना अभी दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और इसका असली दायरा अभी भी अनिश्चित है। 6 अमेरिकी नागरिकों के वायरस के संपर्क में आने की सूचना मिली है। इबोला के अधिकतर मामले छोटे स्तर के ही होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ द्वारा जारी किए गए एक मॉडल के अनुसार, इबोला के बहुत से मामले पकड़ में नहीं आए हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामलों की संख्या 1,000 से अधिक है। दरअसल, मौजूदा

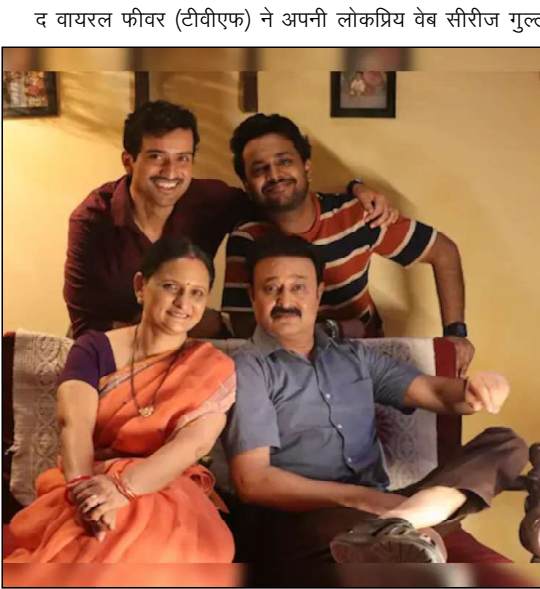
जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर प्रशंसकों को तोहफा, ड्रैगन से सामने आई पहली खूंखार झलक



बोल रहा हो. टीजर में जूनियर एनटीआर को अफगान ट्रेडिंग कंपनी के मुख्य हत्यारे लूगर के रूप में पेश किया गया है, जो एक जटिल और नैतिक रूप से संदिग्ध चरित्र का संकेत दे रहा है. अनिल कपूर रघुवीर राठौड़ के रूप में नजर आते हैं, जो भारत के नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रमुख हैं, और शक्तिशाली ताकतों के बीच एक तेज-तर्रार टकराव की स्थिति पैदा करते दिखते हैं.

इस झलक से अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बीच चल रहे एक बड़े संघर्ष का भी संकेत मिलता है, जो कपीटिटर, हिंसा और बदलती सोच से भरी दुनिया की झलक दिखाता है. कहानी अफीम युद्ध पर बेस्ड है. ड्रैगन जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के बीच पहला कोलेब्रेशन है, जो केजीएफ फिल्मों के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इस पैन इंडिया फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स ने किया है. फिल्म में जूनियर एनटीआर और अनिल कपूर के अलावा बीजू मेनन, रुविमणी वसंत, खुशबू सुंदर और गुरु सोमसुंदरम भी अहम रोल में हैं. यह फिल्म 11 जून, 2027 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

गुल्लक 5 का ऐलान हुआ, शो राजा शिवाजी दुनियाभर में छाप रही में अनंत वी. जोशी की एंट्री, अन्नू ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है मिश्रा के किरदार में आएंगे नजर रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म



द वायरल फीवर (टीवीएफ) ने अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज गुल्लक के 5वें सीजन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। निर्माताओं ने सीरीज का टीजर जारी किया है, जिसने फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है। टीजर में अन्नू भड़्या उर्फ अन्नू मिश्रा का किरदार सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, जिसे अनंत वी जोशी निभा रहे हैं। दरअसल, पिछले 4 सीजन से इस किरदार को वैभव राज गुप्ता निभाते हुए दिखाई दे रहे थे।

सोनी लिव ने गुल्लक सीजन 5 का टीजर जारी करते हुए लिखा, वही रंगत, वही आदतें, वही शरारतें.. अब पहचान तो हो गई इनकी! हमारे अन्नू मिश्रा फिर आ रहे हैं नए किस्से लेकर, अपने प्यारे मिश्रा परिवार के साथ। बता दें, अनंत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय (2025) से लोकप्रियता मिली थी। वहीं जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी और हर्ष मयार अपने किरदार में वापसी करेंगे। गुल्लक 5 की रिलीज तारीख का आना बाकी है। जहां गुल्लक के पिछले चारों सीजनों को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला, वहीं इसके पांचवें सीजन का इंतजार अपने चरम पर था. अब, यह इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है और कैप्शन में लिखा है –

ऐसा लग रहा है... मिश्रा निवास में कुछ बदल गया है... आपको भी समझ आ रहा है क्या? श्गुल्लक्य भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पसंदीदा ओटीटी शोज में से एक है. अपनी शानदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है. वहीं, नए सीजन में परिवार की पुरानी मिठास के साथ नई कहानियां और मोड़ देखने को मिलेंगे.



ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कमाल परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में शानदार कारोबार किया है और ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है. वर्ल्डवाइड तो ये धड़धड़ रि कॉर्ड अपने नाम कर रही है. अब इसने रितेश देशमुख की हाउसफुल को मात देते हुए एक नई बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

हिंदी भाषी क्षेत्र में कई फिल्मों से मुकाबले के बावजूद, रितेश देशमुख स्टारर और निर्देशित ये फिल्म अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

रिपोर्ट के मुताबिक, राजा शिवाजी ने रिलीज के 19वें दिन सभी भाषाओं में मिलाकर 1.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. बता दें कि मंगलवार को इसकी कमाई में टिकटों पर छूट की वजह से मामूली उछाल देखने को मिला. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में राजा शिवाजी के 19 दिनों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 95.7 करोड़ रुपये (नेट) हो गया है. वहीं चौथे वीकेंड तक राजा शिवाजी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर जाएगी और ऐसे कर मराठी सिनेमा की पहली 100 करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी. बता दें कि टैक्स सहित इसका कुल कलेक्शन 112.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. विदेशों में भी राजा शिवाजी का डंका बज रहा है. इसी के साथ इसने ओवरसीज में 4.90 करोड़ रुपये की ग्राँस कमाई कर ली है. वहीं भारत और ओवरसीज की कमाई को मिलाकर राजा शिवाजी का 19 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 117.82 करोड़ रुपये हो चुका है. यह ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा अब हाउसफुल (2010) के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को तोड़ने और रितेश देशमुख की अब तक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने से सिर्फ 5.78 करोड़ रुपये दूर है.

गर्मियों के लिए परफेक्ट हैं ये 5 फेस मिस्ट, जानिए बनाने का तरीका



गर्मी के कारण त्वचा पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में त्वचा को ठंडक देने के लिए आप बाजार से फेस मिस्ट खरीद सकते हैं, लेकिन उनमें मौजूद अप्राकृतिक रंग और खुशबू त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मिस्ट बनाने का तरीका बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आपकी त्वचा को ठंडक और नमी मिलेगी।

खीरे का फेस मिस्ट: खीरे का फेस मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में खीरे को अच्छे से पीसें, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें। जब भी आपको लगे कि गर्मी से आपकी त्वचा काफी बेजान हो गई है, तो उस पर खीरे के फेस मिस्ट का छिड़काव करें। यह फेस मिस्ट त्वचा को पोषण देने के साथ उसे ठंडक भी देगा। खीरे के इस फेस मिस्ट से आपकी त्वचा को ताजगी मिलेगी।

गुलाब जल और नींबू का फेस मिस्ट: गुलाब जल और नींबू का फेस मिस्ट न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि इसे नमी भी देता है। इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे गुलाब जल के साथ नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट त्वचा को ठंडक देने के साथ इसे ताजगी भरा भी महसूस कराएगा। गुलाब जल और नींबू का यह मिस्ट आसकी त्वचा को तरोताजा बनाए रखेगा।

एलोवेरा और खीरे का फेस मिस्ट: एलोवेरा और खीरे का फेस मिस्ट आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ—साथ उसे नमी भी देता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे एलोवेरा जेल के साथ खीरे का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट त्वचा को पोषण देने के साथ इसे ताजगी भरा भी महसूस कराएगा। एलोवेरा और खीरे का यह मिस्ट आपकी त्वचा को नमी देगा।

पुदीना और नारियल पानी का फेस मिस्ट

पुदीना और नारियल पानी का फेस मिस्ट गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें मौजूद पुदीने की ताजगी और नारियल पानी की ठंडक आपकी त्वचा को तरोताजा रखती है। इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे पुदीने के पत्ते डालें, फिर उसमें नारियल पानी डालकर अच्छे से हिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ—साथ उसे नमी भी देगा।

गुड़हल फूल का फेस मिस्ट

गुड़हल फूल का फेस मिस्ट आपकी त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल फूल की पंखुड़ियों को पानी में उबालें, फिर इस मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इसे अपने चेहरे पर छिड़कें। इन फेस मिस्ट के इस्तेमाल से आप गर्मियों में तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी त्वचा भी खिली—खिली रहेगी।